भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2382
19 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

ओडिशा में हरित और कम कार्बन वाले इस्पात प्रौद्योगिकी को बढ़ावा

2382 श्री मानस रंजन मंगराज:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ओडिशा के इस्पात संयंत्र वायु, जल और भूमि प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन कर रहे हैं;
(ख) पिछले तीन वर्षों में अनुपालन को लेकर दर्ज किए गए उल्लंघनों की संख्या कितनी है; और
(ग) राज्य में हरित और कम कार्बन वाले इस्पात प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा ने ओडिशा में इस्पात संयंत्रों के प्रचालन हेतु डिस्चार्ज और उत्सर्जन के लिए पर्यावरणीय मानक निर्धारित किए हैं। बोर्ड ऑनलाइन निगरानी प्रणाली का उपयोग करके तथा भौतिक निरीक्षण और निगरानी प्रणाली के माध्यम से उत्सर्जन और अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है। उल्लंघन के मामलों में जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत उचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) पिछले 3 वर्षों अर्थात 2023-24, 2024-25 और 2025-26 के दौरान रिपोर्ट किए गए उल्लंघनों की सूची इस प्रकार है:-

वर्ष	**सहमति की शर्तों का अनुपालन न करने पर जारी किए गए कारण बताओ नोटिस और निदेश**	**बंद करने हेतु जारी निदेश**
2023-24	50	00
2024-25	59	05
2025-26 (आज की स्थिति के अनुसार)	16	09
कुल	**125**	**14**
स्रोत: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा		

जारी...2/-

(ग) ओडिशा राज्य सहित देश में ग्रीन और निम्न कार्बन इस्पात प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का विवरण निम्नानुसार है:-

i. इस्पात मंत्रालय ने कम उत्सर्जन वाले इस्पात को परिभाषित और वर्गीकृत करने के लिए मानक प्रदान करने हेतु ग्रीन स्टील के लिए वर्गीकरण जारी किया है।

ii. इस्पात मंत्रालय ने इस उद्देश्य के लिए इस मंत्रालय द्वारा गठित 14 कार्यबलों की सिफारिशों के अनुरूप "ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया: रोडमैप एंड एक्शन प्लान" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, जो वर्ष 2070 तक नेट-जीरो लक्ष्य की ओर ग्रीन स्टील और संधारणीयता के लिए भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। यह रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

iii. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत इस्पात क्षेत्र में हाइड्रोजन के उपयोग के लिए पायलट परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु चार पायलट परियोजनाएं प्रदान की गई हैं।

iv. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जनवरी, 2010 में शुरू किया गया राष्ट्रीय सौर मिशन, सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देता है और इस्पात उद्योग के उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करता है।

*****